भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 79

01.12.2025 को उत्तर के लिए

वन क्षेत्र में भारत की रैंकिंग

79. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा अपने वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 में कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत को दुनिया में नौवां स्थान दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त आकलन के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का ब्यौरा क्या है और पिछली रिपोर्ट से इसकी तुलना क्या है;

(ग) प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई 'एक पेड़ माँ के नाम' पहल, अपने आरंभ से अब तक देश में वन क्षेत्र बढ़ाने में किस हद तक सफल रही है; और

(घ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई/की जा रही अन्य प्रमुख पहलों और योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ख) संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के वैश्विक वन संसाधन आकलन (जीएफआरए) 2025, जो 22 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था, के अनुसार भारत को कुल वन क्षेत्र के मामले में दुनिया में नौवें स्थान पर रखा गया है। यह पिछले आकलन की अपेक्षा एक सुधार है, जिसमें भारत को दसवें स्थान पर रखा गया था।

इसके अतिरिक्त, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, देश में वन और वृक्षों के आवरण का आकलन द्विवार्षिक रूप से करता है और इसके निष्कर्ष भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित होते हैं। वन आवरण का आकलन एक समग्र मानचित्रण प्रक्रिया है ,जो रिमोट सेंसिंग पर आधारित है और यह राष्ट्रीय वन सूची से गहन जमीनी सत्यापन और क्षेत्र डेटा द्वारा समर्थित है। आईएसएफआर 2023 के अनुसार, देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है।

(ग) से (घ) विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर और वर्तमान वर्ष में भी देश भर में वृक्षारोपण गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक वृक्षारोपण अभियान "एक पेड़ मां के नाम# प्लांट4 मदर" शुरू किया गया है। यह अभियान देश में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ "संपूर्ण सरकार" और "संपूर्ण समाज" दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। इस अभियान ने देश में हरित आवरण को बढ़ाने में सहायता करते हुए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का योगदान दिया है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय देश में वनों के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे कि राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), वनाग्नि निवारण और प्रबंधन योजना (एफपीएम), नगर वन योजना (एनवीवाई), वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास और तटवर्ती आवासों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) के तहत प्राप्त धन शामिल है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (काम्पा) के अंतर्गत भी वनीकरण किया जाता है। विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान किए गए धन, राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रयासों का समर्थन करते हैं ताकि पारिस्थितिक बहाली उपायों जैसे कि वन क्षेत्रों के भीतर और बाहर वनीकरण, वन परिदृश्य बहाली, पर्यावास सुधार, मिट्टी और जल संरक्षण, सुरक्षा कार्यकलापों और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से वन और वृक्षों के आवरण को बढ़ाया जा सके।

*****